वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) :(क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1990–92 की अवधि के दौरान अनिवासी भारतीयों से प्राप्त स्वीकृत निवेश प्रस्ताव इस प्रकार हैं :–

वर्ष	करोड़ रुपए में
1990	5.24
1991	19.70
1992	439.13

(ग) जी, नहीं। सभी अनिवासी भारतीय निवेशक चाहे वह बड़े हों अथवा छोटे, समान लाभ पाने के हकदार हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) अनिवासी भारतीयों को दी गई रियायतों में ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं:

1 अनिवासी भारतीयों और समुद्रपारीय निगमित निकाय को मुख्य रूप से उनके स्वामित्व में हैं, को कतिपय शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन उच्च प्राथमिकता और अन्य उद्योगों में निवेशित पूंजी के पूर्ण प्रत्यावर्तन और उस पर अर्जित आय सहित शत-प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी के निवेश की अनुमति दी जाती है। जिन अतिरिक्त क्षेत्रों में, शत-प्रतिशत अनिवासी भारतीय निवेश की अनुमति प्रत्यावर्तन लाभों के साथ दी गई है, उनमें पर्यटन, अस्पताल और निर्यातोन्मुख इकाइयां शामिल हैं।

2 अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों को कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों के अन्तर्गत स्टाक एक्सचेंजों में उदघृत इक्विटी शयर परिवर्तनीय ऋण पत्रों में निवशित पूंजी और उससे अर्जित आय पर पूर्ण प्रत्यावर्तन लाभों के साथ "पोर्टफोलियो" निवश करने की सुविधा प्रदान की गई है।

3 प्राथमिक पूंजी मेंबाजारों अनिवासी भारतीयों/समुद्रपारीय निगमित निकायों के लिए "स्टाक इनवेस्ट" स्कीम उपलब्ध है।

4 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना गृह-सम्पत्ति प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त अब जमीन जायदाद, आवासीय और इसके आधारभूत संरचना जैसे पूर्व वर्जित क्षेत्रों में अप्रत्यावर्तन आधार पर शत-प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय निवश की अनमति दी गई है।

राजस्थान में दूरदर्शन केन्द्रों का खोला जाना

*447. **श्री मूलचन्द मीणा :**
श्री इकबाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उच्च और कम शक्ति के ट्रांसमीटर वाले दूरदर्शन केन्द्र खोलने के लिए राजस्थान के किस-किस स्थान का चयन किया गया है ;

(ख) इस संबंध में जिला-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के (क) से (घ) राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : राजस्थान में टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना हेतु राजस्थान सरकार सहित विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। हालांकि देश में 1992–93 के

दौरान टी०वी० ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिए स्थलों को अंतिम रूप दे दिया गया है, परन्तु आठवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के लिए ऐसे स्थानों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। सातवीं योजना की चालू स्कीमों तथा 1990–91 1991–92 तथा 1992–93 की वार्षिक योजनाओं के भाग के रूप में राजस्थान में इस समय स्थापित किए जा रहे/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित टी०वी० ट्रांसमीटरों के स्थलों का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर का स्थल	अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर का स्थल
अजमेर	अजमेर*	—
जोधपुर	जोधपुर *	—
बाड़मेर	बाड़मेर	—
जैसलमेर	जैसलमेर	—
गंगा नगर	अनूपगढ़	भद्रा, रावतसर
उदयपुर	—	देवगढ़, कुंभलगढ़
बूंदी	बूंदी	—
चूरू	—	सुजानगढ़ श्रीडूंगरगढ़ रतनगढ़
झुनझुनू	—	चिरावा
चित्तौड़गढ़	—	बारीसदरी रेल मोगरा*
झालावाड़	—	चौमहला
सीकर	—	फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़
सवाई माधोपुर	—	हिम्दौन
बारन	—	बारन
भीलवाड़ा	—	गंगापुर
नागौर	—	कुछामें*
राजसमुंड	नाथ द्वारा	अमेट*

*स्थापना के लिये परिकल्पित ।

Strategy for stability in trade of cotton

*448. SHRI SOM PAL: Will the Minister of TEXTILES be leased to state:

(a) what is the quantity of cotton imported during the past three years;

(b) whether Government are considering any strategy to make its presence more stable in the international market;

(c) what are the major problems in regular export of cotton; and

(d) what steps are being taken to overcome these?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) The Government has not imported cotton during the last three years. However, under the Advances Licensing Scheme private mills have imported cotton to the tune of 3.00 lakh bales in the cotton year 1991-92.

(b) to (d) Government has a policy of exporting a minimum of 5 lakh bales of cotton at the commencement